[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

आपको फायदा पहुंचाना चाहता है तो स्टेट ओनरशिप के बेसिस पर आप उन्हें साझीदार बनाइये। जहां ओनरशिप आपके हाथ में रहता है और कमिशन के तौर पर आप लोगों को देते हैं लीज के रूप में न दें और उनको ओनर न बनायें तो आपको बहुत ज्यादा यह शिकायतें नहीं सुनने को मिलेंगी ।

18.00 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

EIGHTY-SIXTH REPORT

Shri Hem Raj (Kangra): Sir, I beg to present the Eighty-sixth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions.

18.01½ hrs.

DE-SCHEDULING* OF SCHEDULED CASTES

Mr. Chairman: We will now take up the half-an-hour discussion.

श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जमातों की सूची के संशोधन और अनुसूचित जातियों के अनुसूची से निकाले जाने के बारे में चर्चा उठाने का मुझे जो अवसर दिया उसके लिए मैं आपका अभिनन्दन करता हूं और मैं शुरू में ही यह बात कहना चाहता हूं कि बहुत दिन से यह मामला पड़ा हुआ है ।

सभापति महोदय : हाफ ऐन आवर डिस्कशन के बाद हम आधा घंटा और बैठ सकते हैं । अगर आपकी इच्छा हो तो आप बैठे रह सकते हैं ।

श्री न० प्र० यादव (सीतामढ़ी) : मैं दो घंटा तक बैठने के लिए तैयार हूं । मुझे टाइम ही नहीं मिला है । (**व्यवधान**)..

श्री दे० शि० पाटिल : इस मंत्रालय का भार जिन्होंने संभाला है वह आदर्णीय श्रीमती चन्द्रशेखर स्टेट वाइज मीटिंग रख कर बहुत जल्दी यह सवाल हल करने की कोशिश कर रही है । उसके लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूं । दो सवाल इसमें आते हैं सभापति जी। एक तो प्रादेशिक प्रतिबंध हटाने का और सूची का परीक्षण करने का है । जो लिस्ट बनायी जाती है वह स्टेट-वाइज लिस्ट रहती है लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कि आसाम, केरल मध्य प्रदेश और विदर्भ में शिड्यूल्ड और नान-शिड्यूल्ड एरिया ऐसी लिस्ट बनायी जाती है । शिड्यूल्ड एरिया में जो लोग रहते हैं उनको तो शिड्यल्ड ट्राइब माना जाता है । लेकिन शिड्यूल्ड एरिया के बाहर जो लोग रहते हैं उनको आदिवासी या शिड्यूल्ड ट्राइब नहीं माना जाता है । इसका परिणाम यह होता है कि मेम्बर आफ दि सेम कास्ट अगर शिड्यूल्ड एरिया के बाहर रहता है तो आदिवासी नहीं माना जाता है और इस का परिणाम यह होता है कि उसको किसी भी केन्द्रीय स्कीम का फायदा नहीं मिलता इस एरिया रेस्ट्रिक्शन की वजह से । सभापति महोदय, मेम्बर्स आफ दि सेम फेमिली में भी डिस्टिंक्शन किया जाता है । अगर पिता शिड्यूल्ड एरिया में रहता है तो शिड्यूल्ड ट्राइब माना जाता है, लेकिन अगर उसका लड़का शिड्यूल्ड एरिया के बाहर रहता है तो वह आदिवासी नहीं माना जाता है और इस कारण कोई भी एजूकेशनल फैसिलिटी या एम्प्लायमेंट

*Half-An-Hour Discussion.

की फैसिलिटी उसको नहीं मिल पाती । इस शिड्यूल्ड एरिया और नान-शिड्यूल्ड एरिया के रेस्ट्रिक्शन की वजह से विदर्भ में आदिवासियों की 14 लाख पापुलेशन है लेकिन उनमें से केवल 2 लाख 35 हजार आदिवासियों को वेलफेयर स्कीम्स का फायदा और कन्सेशन वगैरह मिल पाता है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रिमूव एरिया रेस्ट्रिक्शन । इस के लिए सब स्टेट्स ने भी अपनी ओपिनियन दी है और संसद् ने भी अपनी ओपिनियन दी है कि यह एरिया रेस्ट्रिक्शन रिमूव होना चाहिए और पंडित जी का भी कमिटमेंट है । दूसरी बात यह है कि जो लेफ्ट आउट ट्राइबल्स हैं जो कि वर्तमान लिस्ट में नहीं हैं लेकिन उसमें आ सकते हैं उनको लिस्ट में लेना चाहिए । आश्चर्य की बात यह है कि सूची में शामिल करने की कसौटी होते हुए भी कुछ जातियां विदर्भ में ऐसी हैं जिनको आदिवासियों में नहीं रखा गया है जैसे बनजारा, मोई या धीवर या कोली, बुराद, गोवारा । इनके बारे में मैंने कहा था कि उसका संशोधन करना चाहिए और इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब सूची में रखना चाहिए ।

चौथी बात यह है कि जहां तक डी-शिड्यूलिंग की बात है कुछ जातियां जो अनटचेबिल्स नहीं हैं लेकिन वह शिड्यूल्ड कास्ट में हैं । दे आर नाट सफरिंग फ्राम अनटचेबिलिटी । ऐसी जो जातियां हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट में रखी गई हैं । बनजारा एक जाति है जो अनटचेबिल नहीं है । दे आर नाट सफरिंग फ्राम अनटचेबिलिटी। लेकिन उसे उन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट में रखा है । दिल्ली पंजाब, राजस्थान और त्रिपुरा में उनको शिड्यूल्ड कास्ट में रखा है । लेकिन वह अनटचेबिल नहीं हैं । गाल और बिहार में वह शिड्यूल्ड ट्राइब हैं लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डी-नोटिफाइड एरिया में रखा है और मद्रास केरल और आसाम में नाट फाउंड करके कोई सूची में नहीं रखा है । तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ही जाति जो अनटचेबिल नहीं है उसको शेड्यूल्ड कास्ट में रखा है । शेड्यूल्ड ट्राइब होते हुए भी डी-नोटिफाइड ट्राइब में, और कहीं शिड्यूल्ड ट्राइब में रखी गई है । यह राष्ट्रीय हित में नहीं है । एक ही जमात, एक सरीखा उनका परिवार, एक सरीखा रहन-सहन होने पर भी उनको प्रत्येक राज्य में अलग-अलग तरह से रखना यह राष्ट्रीय हित में ठीक नहीं है और इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी छानबीन करके बंजारा को शिड्यूल्ड ट्राइब में रखना चाहिए । दो ही प्वाइंट मैंने आपके सामने रखे हैं । कितने दिनों से हम लोग इसके लिए परेशान हैं ? पंडित जी का कमिटमेंट इसके लिए है कि एरिया रेस्ट्रिक्शन बिलकुल रिमूव होना चाहिए क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को स्कालरशिप वगैरह की फैसिलिटीज नहीं मिल पातीं । Their application has been rejected on the ground that they reside outside the scheduled area. इसलिए इसके लिए एक बिल लाने की सख्त जरुरत है क्योंकि यह कानूनी बात है । सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है कि इसमें कानून में संशोधन किये बगैर यह हो नहीं सकता । इसलिए पार्लियामेंट में इसके लिए एक बिल लाने की जरूरत है । मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इसी सेशन में बिल ले आना चाहिए और यही कारण था कि मैंने इस पर चर्चा उठायी थी । मैं बहुत ही तीन चार साल से इसके लिए प्रयत्न कर रहा हूं । बहुसंख्या आदिवासी आउट आफ दि शिड्यूल्ड एरिया है । हरएक प्रान्त में शिड्यूल्ड एरिया के बाहर जो रहते हैं उनको कोई फायदा किसी स्कीम का नहीं मिलता है इसलिए बिल लाने की जरूरत है । मैं

[श्री दे० शि० पाटिल]

आपके द्वारा मंत्रालय से यही प्रार्थना करता हूं कि इसी सेशन में बिल लाकर के उसका फायदा सब आदिवासियों को दे दिया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) चेयरमैन महोदय, मैं यह महसूस करता हूं . .

सभापति महोदय : आप सवाल करें ।

श्री स० मो० बनर्जी : दस मिनट का समय

सभापति महोदय : जो कन्वेंशन है उसी पर चलिए आप ।

Shri S. M. Banerjee: That is true, but the convention is that if he does not take ten minutes then we can divide our time, five minutes each.

Mr. Chairman: I may tell the hon. Member that there are a number of other signatories also.

Shri S. M. Banerjee: Then I would only ask a question. There is a lurking fear in the minds of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Uttar Pradesh and other places that some of the castes belonging to either Scheduled Castes or Scheduled Tribes are likely to be descheduled; for instance, the *dhobis* and *chamars* are likely to be de-scheduled. I want a definite assurance from the hon. Minister that as a result of the implementation or acceptance of the Lokur Committee's recommendation no caste is going to be de-scheduld; rather, further castes will be added to it.

18.07 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*].

There should be uniformity. *Dhobi* in Uttar Pradesh is a Scheduled Castc; *Dhobi* in other places may not be a Scheduled Caste. So, there should be uniformity. But I want an assurance that no caste is likely to be de-scheduled.

Shri Sonavane (Pandharpur): When does the Government propose to place the Report of the Lokur Committee on the Table of the Lok Sabha and is it the intention of Government to remove such of the castes from the list of Scheduled Castes who are not Scheduled Castes on the ground of untouchability and include such castes who suffer from untouchabality, social disabilities, in the list that would be revised hereafter?

श्री हुकम चन्द कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी सवाल पूछने दीजिए, मैंने लिख कर दिया है, नोटिस दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम नहीं है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : आधे घंटे की चर्चा जब प्रारम्भ होती है तो नाम लिख कर दिये जाते हैं, हमने नाम दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले नहीं दिया है, बाद में दिया है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : पहले दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा, पूछ लीजिए ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं जानना चाहूंगा माननी मंत्री जी से मुझे यह तो पूरा विश्वास है कि मंत्री जी शिडयूल्ड कास्ट के लोगों और पिछड़ी जाति वालों के प्रति काफी हमदर्द हैं और उनकी उन्नति चाहती है लेकिन इतने प्रयत्न करने के बाद भी क्या सरकार यह बतलायेगी कि इनकी उन्नति के लिए राज्य सरकारें साथ नहीं देती हैं या इनकी उन्नति करने के जो तरीके हैं उनमें कोई त्रुटि है यदि हां, तो उसको दूर करने के लिए जो अलग-अलग राज्यों को पैसा दिया जाता है और वह ठीक तरह से राज्य सरकारें इन्तजार

नहीं करती हैं, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

Shri S. C. Samanta (Tamluk): Is it not a fact that the scheduled caste people themselves are trying to come at par with the higher castes and, if so, why all the scheduled caste organisations in the country were not consulted by the Lokur Committee in order to come to a reasonable decision?

Shri Chuni Lal (Ambala): May I put a question?

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I want to put a question, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: You must give notice before the discussion begins.

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अभी बहुत समय बाकी है इसलिए 1,1 मिनट के सवाल पूछ लेने की आज्ञा दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माफ कीजियेगा जिन्होंने नोटिस दिये हैं केवल वही सवाल पूछ सकते हैं ।

श्री बाल्मीकी : समय अभी काफी बच रहता है . . . .

Mr. Deputy-Speaker: Under the rules, notice should be given before the discussion begins.

श्री बाल्मीकी : उस नियम की मुझे जानकारी है लेकिन मेरी आप से प्रार्थना है कि आप इस पर 1,1 मिनट के सवाल पूछने की इजाजत दे दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : माफ कीजियेगा ऐसे नहीं हो सकता है ।

श्री बाल्मीकी : मेरी आप से प्रार्थना है कि समय बाकी रहता है इसलिए . . .

Mr. Deputy-Speaker: The rule is: Any Member who has previously intimated to the Speaker may be permitted to ask a question. You cannot ask a question any time you like.

The Deputy Minister in the Department of Social Welfare (Shrimati Chandrasekhar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the hon. Member, Mr. Patil, who raised this Half-An-Hour Discussion brought out two main points. Firstly, he said that there are area restrictions which prevent some of the tribes who live in the same State from enjoying the benefits of the scheduled tribes which are available from the backward class sector programmes and that area restrictions should be removed. Secondly, he said that there are certain anomalies in the existing List, that is, some people who belong to the scheduled castes and scheduled tribes and who suffer from untouchability are not included and some, by mistake, have been included and that those anomalies should be removed.

Sir, I have, time and again, answered questions on this point. As I have said earlier, there is no disagreement with the Members. I think, if I remember aright, on the 25th February this year, I already said that when the meetings were held on the 9th and 10th December, with both the Members of Parliament and the Ministers belonging to the scheduled castes and tribes, there was a general agreement about the removal of area restrictions.

Along with this area restriction, as he pointed out, there are certain anomalies which should also be removed. This can be done by revising the existing List. If the revision of the List of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has to be taken up under articles 341 and 342 of the Constitution, we have to do this by bringing in a legislation before Parliament. If a legislation has to be brought in to bring these changes, there is no point in bringing a legislation for the re-

[Shrimati Chandrasekhar]

movel of area restrictions first and then again for the anomalies to be set right.

As the Members are aware, we have been holding meetings with the Members of Parliament and Ministers of each State who belong to the scheduled castes and scheduled tribes. We have almost completed the List. Only a few States are remaining, that is, Kerala, Jammu and Kashmir and, I think, Andaman and Nicobar Islands also and that too because those Members were not present or could not come over for the discussion. Otherwise, all our discussions are over. During the discussions, we came across certain points of difference and we have referred this matter to the various State Governments for clarification. As soon as that is received, I think, we will be able to bring in a legislation and if Parliament has time to take up that legislation, I think, we will be ready to bring the Bill in the current session itself.

Sir, apart from that, I do not think I can give any assurance that these castes will be included and those castes will be removed or these tribes will be included and those tribes will be excluded. For example, in U.P., there are Adivasis but they have not been listed in the existing List. We are really keen that we should bring in the legislation as early as possible so that those people who have been left out, those who suffer by the area restriction, be included in the List and allowed to receive the benefits.

As to the question of Mr. Banerjee about *dhobis*, his point of view is that all *dhobis*, just because *dhobis* of Uttar Pradeh and some other States are considered to be the scheduled castes, should be included in the list of scheduled castes. The criterion for including any caste in the List is whether they suffer from untouchability or not. If any particular group of *dhobis* in any State suffers from untouchability, we will certainly include it in the list of scheduled castes. If they do not suffer from untouchabality and if they themselves do not want to be classified as scheduled castes, I do not think there is any reason why we should class them a scheduled castes, as Mr. Patil has rightly pointed out.

About the lurking fear of members that we are keen on removing certain communities from the list for reasons which they themselves know, I do not think there is any need for any such fear. We were holding meetings State-wise mainly because we wanted to give more opportunities to the members to voice their feelings and tell us as to how they feel about certain communities in the list being taken out of the list and how the anomaly is to be removed. Another thing is that the lists are drawn up State-wise. So we had been holding meetings State-wise. Unfortunately Mr. Sonavane was not present in the meeting; if he had been present he would not have put this question.

Shri Sonavane: I only wanted to know whether the report would be placed on the Table.

Shrimati Chandrasekhar: We have a number of reports. This question is hanging fire for some years. We had been getting information from the State Governments. There were certain anomalies and the Minister of Social Security felt that a Committee should be appointed to go and visit the various States to find out how they felt about the anomalies. The Committee has submitted a report. That is one of the documents which we have in our possession to finalise our views; it is not the bible for us to take all the recommendations from the Lokur Committee's report. The report is available: most of the members belonging to scheduled castes and scheduled tribes, who are interested in the recommendations, have got it. . . .

Shri Sonavane: Let the whole House be interested in it.

Shrimati Chandrasekhar: It will be placed in the Library and all the members who are interested in it can have a study of it.

Because the time at their disposal was very short,—they were to submit a report within three months and they had to visit all the States—the Lokur Committee could not meet all the representatives as Mr. Samanta desired; I also would have desired that they meet many a member who had some contact with the communities—scheduled castes and scheduled tribes.

Shri S. C. Samanta: The scheduled caste organisations were not contacted.

Shrimati Chandrasekhar: They could have contacted the organisations. They had a certain plan. They were asked to go to the various States and examine. They could not meet all those organisations, because they did not probably have enough time. Since we are keen on introducing the legislation, I do not think I can add anything more.

Shri D. C. Sharma: When will the legislation be introduced?

18.20 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now resume further discussion on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. Now, Shri Chandak.

Shri Chandak (Chhindwara) *rose*—

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं सदन में गण पूर्ति नहीं है।

Mr. Deputy-Speaker: There is no quorum. The bell is being rung...The bell has stopped ringing. There is no quorum. The House will now stand adjourned and meet again at 11 A.M. tomorrow. The hon. Minister will reply tomorrow.

18.21 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 21, 1966/Vaisakha 1, 1888 (Saka).

GMGIPND—LS II—312(Ai), LSD—5-7-66—970.